इस्पात क्षेत्र का एक परिदृश्य

वैश्विक परिदृश्य । घरेलू परिदृश्य । उत्पादन । मांग – उपलब्धता प्रक्षेपण । इस्पात की कीमतें । आयात । निर्यात । लोहा और इस्पात पर कर-वसूली । निजी क्षेत्र में लोहा और इस्पात की वृद्धि के अवसर ।

वैश्विक परिदृश्य

- वर्ष 2014 में विश्व में क्रूड स्टील का उत्पादन बढ़कर 1665 मिलियन टन (एमटी) हो गया है तथा इसमें वर्ष 2013 से 1% की वृद्धि हुई है ।
- वर्ष 2014 में चीन विश्व का सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक (823 एम टी)राष्ट्र बना रहा तथा उसके पश्चात क्रमश: जापान (110.7 एमटी), संयुक्त राष्ट्र अमरीका (88.2 एमटी) का स्थान रहा और इसमें भारत (86.5 एमटी) चौथे स्थान पर रहा।
- डब्ल्यूएसए ने प्रक्षेपित किया है कि भारतीय इस्पात की मांग में वर्ष 2015 में 6.2 प्रतिशत और वर्ष 2016 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि इस्पात की वैश्विक उपयोग में क्रमश: 0.5 प्रतिशत ओर 1.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इन दोनों वर्षों में चीन के इस्पात उपयोग में 0.5 प्रतिशत की गिरावट प्रक्षेपित है।
- डब्ल्यूएसए द्वारा वर्ष 2014 में फिनिश्ड स्टील की प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक स्तर पर 217 किलो–ग्राम और चीन में 510 किलो-ग्राम रहने का अनुमान लगाया गया है।

(नोट : 2014 संबंधी आकड़े अनंतिम हैं और ये आंकड़े जून, 2015 में डब्ल्यूएसए द्वारा प्रकाशित 'वर्ल्ड स्टील इन फीगर्स 2015' से लिए हैं)

घरेलू परिदृश्य

- भारतीय इस्पात उद्योग ऊँची आर्थिक वृद्धि और इस्पात की बढ़ती हुई मांग के साथ वर्ष 2007-08 से विकास की नई अवस्था में प्रवेश कर चुका है।
- उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप भारत विश्व में क्रूड इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बन गया है और यह स्पंज आयरन अथवा डी आर आई का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु इस्पात संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनमें देश में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत में बढ़ोतरी की संभावनाएं निहित है। इसमें अन्य के साथ निम्न शामिल है –लगभग एक ट्रिलियन डॉलर के अवसरंचना निवेश का अनुमान है, विनिर्माण की प्रक्षेपित वृद्धि दर के वर्तमान 8% से बढ़कर 11-12% होने का अनुमान है, वर्ष 2030 तक शहरी जनसंख्या 400 मिलियन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 600 मिलियन हो जाएगी, इस्पात के लिए ग्रामीण बाजार का उत्पन्न होना, जो लगभग 10 किलो ग्राम वार्षिक की खपत कर रहा है तथा जिसमें भारत निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी आवास योजना सहित अन्य और योजनाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते बढ़ोतरी होगी।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 को जारी करते समय इसमें इस्पात का उत्पादन वर्ष 2019-20 तक 110 मिलियन टन (एमटी) पहुंचाने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, वर्तमान में चल रही 'ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड' दोनों परियोजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर 12वीं योजना हेतु इस्पात संबंधी कार्यकारी समूह ने यह प्रक्षेपित किया है कि वर्ष 2016-17 तक देश में घरेलू क्रूड इस्पात की क्षमता के 140 एमटी होने की संभावनाएं हैं और यदि सभी आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा किया जाए तो इसके 149 एमटी तक पहुंचने की संभावनाएं हैं।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 को जारी किए जाने के बाद से घरेलू इस्पात उद्योग (आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर) के तीव्र विकास के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थायी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 की समीक्षा की जा रही है।

उत्पादन

- इस्पात उद्योग को वर्ष 1991 और 1992 में क्रमशः लाईसेंस मुक्त और नियंत्रणमुक्त किया गया था।
- वर्तमान में भारत क्रूड इस्पात के क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है।
- वर्ष 2014-15 में बिक्री हेतु कुल 91.46 एमटी फिनिश्ड स्टील (अलॉय +नॉन अलॉय) का उत्पादन किया गया और वर्ष 2013-14 से इसमें 4.3% की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2014-15 में बिक्री हेतु 9.7 एमटी पिग आयरन का उत्पादन किया गया और इसमें वर्ष 2013-14 से 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- भारत कोयला आधारित रूट जो देश में स्पंज आयरन के कुल 90% उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, के साथ स्पंज आयरन का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है।
- पिछले पाँच वर्षों में बिक्री हेतु पिग आयरन, स्पंज आयरन और कुल फिनिश्ड इस्पात (अलॉय+नॉन अलॉय) के उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है:-

भारतीय इस्पात उद्योग : विक्री हेतु उत्पादन (मिलियन टन में)					
श्रेणी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पिग आयरन	5.68	5.371	6.870	7.950	9.694
स्पंज आयरन	25.08	19.63	14.33	18.20	20.38
कुल फिनिश्ड इस्पात (अलॉय+नॉन अलॉय)	68.62	75.70	81.68	87.67	91.46
स्रोत: संयुक्त संयत्र समिति					

मांग – उपलब्धता प्रक्षेपण

- देश में लौह और इस्पात की मांग –उपलब्धता का प्रक्षेपण इस्पात मंत्रालय द्वारा अपनी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में किया जाता है।
- उपलब्धता में कमी को मुख्यत: आयात के जरिए पूरा किया जाता है।
- इस्पात उपभोक्ता परिषद के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ सम्पर्क रखा जाता है, जिसका नियमित आधार पर आयोजित होता है।
- इस सम्पर्क से उपलब्धता संबंधी समस्याओं और गुणवत्ता संबंधी शिकायतों का समाधान करने में सहायता मिलती है।

इस्पात की कीमतें

- दिनांक 16.1.1992 को लोहा और इस्पात के कीमत विनियमन को समाप्त कर दिया गया था। तब से बाजार शक्तियों द्वारा इस्पात की कीमतें निश्चित होती है।
- इस्पात की घरेलू कीमतें अन्य के साथ-साथ कच्ची सामग्री की कीमतों की प्रवृतियों, बाजार में मांग-आपूर्ति की स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की प्रवृतियों द्वारा प्रभावित होती है।

- देश में मुख्य इस्पात निवेशों की निगरानी करने और उनमे समन्वय करने के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय में एक अतंर मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) कार्य कर रहा है ।
- सरकार ने इस्पात की कीमतों के स्थिरीकरण के लिए पूर्व मे अनेक राजकोषीय और अन्य उपाय किए है जैसे पिछले कुछ वर्षों में, इस्पात, प्रमुख कच्ची सामग्रियों सहित खनिज उत्पादों तथा अयस्क एवं संकेन्द्रणों पर आयात शुल्क में पर्याप्त कमी करना। साथ ही, वर्तमान में इस्पात पर उत्पादन शुल्क 12% है और इस्पात मदों पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है । सरकार ने खनिजों के तदर्थ निर्यात को नियंत्रित करने और घरेलू इस्पात उघोग की दीर्घकालिक मांग की पूर्ति के लिए इनका संरक्षण करने के लिए लौह अयस्क के सभी स्वरूपों, निम्न ग्रेडों को छोड़कर, पर 30% और लौह अयस्क पैलेटो पर 5% निर्यात शुल्क भी लगाया है ।
- इस्पात की गुणवता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक मदों को सरकार द्वारा जारी गुणवता नियंत्रण आदेश के अधीन लाया गया हैं।

आयात

- वर्तमान नीति के तहत लोहा और अयस्क का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है
- पिछले 5 वर्षों में फिनिश्ड इस्पात (अलॉय + नॉन अलॉय) के कुल आयात का ब्यौंरा निम्नवत हैं :-

भारतीय इस्पात उद्योग : आयात (मिलियन टन में)					
श्रेणी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल फिनिश्ड इस्पात (अलॉय+नॉन अलॉय)	6.66	6.86	7.93	5.45	9.32
स्रोत: संयुक्त संयत्र समिति					

निर्यात

- लोहा और इस्पात स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य है ।
- पिछले 5 वर्षों में फिनिश्ड इस्पात (अलॉय + नॉन अलॉय) के कुल निर्यात का ब्यौरा निम्नवत हैं :-

भारतीय इस्पात उद्योग : निर्यात (मिलियन टन में)					
श्रेणी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल फिनिश्ड इस्पात (अलॉय+नॉन अलॉय)	3.64	4.59	5.37	5.98	5.59
स्रोत: संयुक्त संयत्र समिति					

लौह और इस्पात पर कर-वसूली

एस डी एफ वसूली

- इस कर-वसूली को इस्पात क्षेत्र के आधुनिकीकरण, विस्तार और विकास के वित्त पोषण के लिए शुरू किया गया था । यह निधि अन्य के साथ साथ निम्न को भी सहायता प्रदान करती है :-
  - एकीकृत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण, पुननिर्माण, विविधिकरण, नवीनीकरण और पुर्नस्थापना के लिए पूँजीगत व्यय ।
  - अनुसंधान एवं विकास
  - एस एस आई निगमों को छूट प्रदान करना
  - जेपीसी के ईआरयू पर व्यय
- एसडीएफ कर वसूली को दिनांक 21.4.1994 से समाप्त कर दिया गया था ।
- मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इस राशि को मुख्य उत्पादकों को ऋण देने के लिए रिसाईकल किया जा सकता है ।
- इस्पात आदि पर आर एण्ड डी को बढ़ावा देने के लिए मुख्य उत्पादकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज को निरस्त कर दिया गया है ।
- इस क्षेत्र में आर एण्ड डी संबंधी प्रयासों के दिशा निर्देशन के लिए एक अधिकारी प्राप्त समिति की स्थापना की गई है ।

- ईजीईएएफ – इस कर वसूली को इंजिनियरिंग निर्यातकों हेतु प्रयुक्त आदानों की लागत में अंतर के भुगतान के लिए शुरू किया गया था । इस निधि व्यवस्था को 19.2.96 को समाप्त कर दिया गया ।

निजी क्षेत्र में लौह और इस्पात की वृद्धि के अवसर

नई औद्यौगिक नीतिगत तंत्र

नई औघोगिक नीति ने निम्न व्यवस्थाओं के जरिए भारतीय लोहा और इस्पात उघोग को निजी निवेश हेतु खोल दिया है – (क) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में से लोहा और इस्पात क्षेत्र को हटाना (ख) अनिवार्य लाईसेंस से इसे मुक्त करना । विदेशी प्रौद्योगिकी के आयातो के साथ-साथ विदेश प्रत्यक्ष निवेश को एक ऑटोमैटिक रूट के तहत कुल सीमाओं तक अब स्वतंत्र रूप से अनुमति प्रदान की गई है । इस उदारीकृत परिदृश्य में इस्पात मंत्रालय की भूमिका एक सुविधादाता की है और यह नए और वर्तमान इस्पात संयंत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश तथा सहायता प्रदान करता है ।

विकास प्रोफाईल

(i) इस्पात : औद्योगिक नीति के उदारीकरण और सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों के तहत इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र के प्रवेश, भागीदारी और विकास पर जोर दिया गया है। जब वर्तमान इकाईयों का आधुनिकीकरण/विस्तार किया जा रहा है, तभी देश के विभिन्न भागों में एक बड़ी संख्या में नए इस्पात संयंत्र भी स्थापित हो रहे है, जो कि आधुनिक, किफायती तथा नवीनतम प्रौद्योगिकियों वाले है। पिछले कुछ वर्षों में मांग पक्ष की तीव्र और स्थायी वृद्धि ने भी घरेलू उद्यमियों को देश के विभिन्न राज्यों में नई ग्रीन फील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है ।

वर्ष 2014-15 में देश में क्रूड इस्पात की क्षमता 109.85 एमटी थी और विश्व में क्रूड इस्पात का चौथा सबसे बड़ा उत्पादन राष्ट्र होने के चलते भारत के पास विभिन्न किस्मों की ग्रेडों का उत्पादन करने की अतंर्राष्टीय गुणवत्ता के मानको वाली क्षमता साख विद्यमान है। देश के शीघ्र ही विश्व में क्रूड इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बनने की संभावना है बशर्ते नई क्षमता के सृजन के लिए सभी आवश्यकताओं को भली भांति पूरा किया जाए ।

(ii) पिग आयरन: भारत पिग आयरन का भी एक मुख्य उत्पादक राष्ट्र है। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में अनेक इकाईयों की स्थापना के साथ न केवल आयात में अत्यधिक गिरावट आई है बल्कि भारत पिग आयरन का एक शुद्ध निर्यातक भी बन गया है। वर्ष 2014-15 में बिक्री हेतु पिग आयरन के कुल उत्पादन का लगभग 91% उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया गया था । वर्ष 1991-92 में बिक्री हेतु पिग आयरन का उत्पादन 1.6 एमटी हुआ था जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 9.7 एमटी हो गया है ।

(iii) स्पंज आयरन: देश के खनिज सम्पन्न राज्यों में स्थित कोयला आधारित इकाईयों के साथ भारत विश्व में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। कालान्तर में कोयला आधारित रुट एक मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उभरा है और देश में स्पंज आयरन के कुल उत्पादन में इसका योगदान 90% है। बाद के वर्षों में स्पंज आयरन के निर्माण क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2014-15 में यह लगभग 46.23 एमटी हो गई।